Executive Summary

The State of Haryana for purpose of regulating and allowing advertisements in the State has brought various policies/ byelaws from the time to time, such as

i. Notified Haryana Municipal (Control on Advertisement) Bye-laws, 2008
ii. The Haryana Municipality Outdoor Advertising Policy, 2010 issued vide memo dated 16.02.2010.
iii. The Haryana Municipal Corporation Advertisement Byelaws, 2016 notified on 28.09.2016 and its subsequent amendment on 08.06.2017.
iv. The Haryana Municipal Corporation Advertisement Byelaws, 2018 notified on 28.03.2018.

The Government in latest has notified the Haryana Municipal Advertisement Byelaws 2022 on 15.07.2022 vide which advertisement on properties of Government entities/ agencies is permitted through Open E-auction only.
For conducting open auction of advertisement sites, an online portal has been launched on 11.10.2022.
Till date, out of total 414 identified advertisement sites, 114 sites have been successfully auctioned, which in total has generated total revenue of Rs. 11.97 Crores.

The Commissioner, Municipal Corporation Gurugram has informed data/ record pertaining to advertisement fees/ charges is not complete/ available. An investigation for missing record is in process. The information provided is as per only available office record.

NOTE FOR PAD

The State of Haryana for purpose of regulating and allowing advertisements within municipal areas has taken following actions:

i. Notified Haryana Municipal (Control on Advertisement) Bye-laws, 2008 exercising the powers conferred by Clause (p) of Section 200 & Section 214 of Haryana Municipal Act, 1973.
ii. The said bye-law was superseded by the Haryana Municipality Outdoor Advertising Policy, 2010 vide memo dated 16.02.2010, which was framed on the basis of advertisement policy of National Capital Delhi.
iii. Since, the policy was lacking parameters for location of advertisement and regulation of advertisements installed by private owners, therefore as per the orders of the Hon'ble High Court in COCP 2695 of 2012, Municipal Corporation, Gurugram appointed Delhi Integrated Multi-Modal Transit System (DIMTS) as consultant to frame the bye-laws as well as prepare a master plan for advertisements. The Government decided that instead of framing advertisement byelaws for only MCG, the byelaws shall be drafted for all Municipal Corporations. Accordingly, the Haryana Municipal Corporation Advertisement Byelaws, 2016 was notified on 28.09.2016 and its subsequent amendment on 08.06.2017.
iv. For simplifying the byelaws, the Government constituted a Committee and as per recommendation of the Committee, the Haryana Municipal Corporation Advertisement Byelaws, 2018 were notified on 28.03.2018, which superseded the Byelaws of 2016.

The Government with the intention to bring more transparency, empowerment to general public and increasing the potential of Government entities/ agencies notified the Haryana Municipal Advertisement Byelaws 2022 on 15.07.2022 with clear direction that advertisement on properties of Government entities/ agencies can only be permitted through Open E-auction for which an online portal has also been launched on 11.10.2022.

The salient features of these byelaws and the portal are:

- All the advertisement entities (company/ trust/ individual) will be registered at State level and once registered are eligible for bidding in all municipalities.
- All permissions and auctions are being managed and monitored through online portal.
- To stop revenue leaks, all the permissions will be active only after the advance Quarterly payment is received by the municipality.
- Private / Other Government Department sites after examination (w.r.t bye-laws) shall be e-auctioned by MC.
- Reserve price to be declared by MC as per the guidelines issued by the Government.
- After successful auction, MC to recover the prevailing notified permission charges which shall be shared in a ratio of 60:40 between owner and MC respectively.
- The permission holder has to submit security deposit equivalent to payment of one quarter to the MC, so that in case of any payment default, the security

deposit will be subsumed. The permission will automatically get cancelled on completion of security deposit.

The portal till date has achieved the followings:

- There are more than 60 entities registered in the portal at State Level
- Till date 414 municipal sites have been e-auctioned, out of which 114 sites have been successfully auctioned
- From these 114 sites, the cumulative successful annual auctioned price is Rs. 11.97 Crores against the reserve price of Rs. 3.86 Crores.
- Haryana Mass Rapid Transport Corporation is also using this platform to auction advertisement on properties of Rapid Metro Rail Gurugram.

The Commissioner, Municipal Corporation Gurugram has informed vide letter dated 20.02.2023 that data/ records pertaining to advertisement fees/ charges of previous years (The record related to old permissions and charges of advertisement for the time period prior to June 2022) is not fully available in the office of MCG. Therefore, the information pertaining to recoverable amount, recovered amount and cause of delay in recovery, is only as per available information only.

Investigation for missing record is under process, which may take time for 6 months.

नोट फॉर पैड

हरियाणा राज्य ने नगरपालिका क्षेत्रों के भीतर विज्ञापनों को विनियमति करने और अनुमति देने के उद्देश्य से निम्नलिखित कार्रवाई की है:

1. अधिसूचित हरियाणा नगरपालिका (विज्ञापन पर नियंत्रण) उपनियम, 2008, हरियाणा नगर पालिका अधिनियम, 1973 की धारा 200 और धारा 214 के खण्ड (पी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।
2. उक्त उपनियम को हरियाणा नगर पालिका आउटडोर विज्ञापन नीति, 2010 द्वारा दिनांक 16.02.2010 द्वारा अधिक्रमित किया गया था, जिसे राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की विज्ञापन नीति के आधार पर बनाया गया था।
3. चूंकि, नीति में विज्ञापन के स्थान और निजी मालिकों द्वारा स्थापित विज्ञापनों के नियमन के लिए मापदंडों का अभाव था, इसलिए सीओसीपी 2695 आफ 2012 में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार, नगर निगम, गुरूग्राम ने दिल्ली एकीकृत मल्टी–मोडल ट्रांजिट सिस्टम (डीआईएमटीएस) सलाहकार के रूप में नियुक्त किया जिसने उपनियम बनाने के साथ–साथ विज्ञापनों के लिए एक मास्टर प्लान तैयार किया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि केवल नगर निगम गुरूग्राम के लिए विज्ञापन उपनियम बनााने के बजाय सभी नगर निगमों के लिए उपनियम बनाए जाएंगे। तदनुसार, हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2016 को 28.09.2016 को अधिसूचित किया गया था और इसके बाद के संशोधन को 08.06.2017 को अधिसूचित किया गया था।
4. उपनियमों को सरल बनाने के लिए, सरकार ने एक समिति का गठन किया और समिति की सिफारिश के अनुसार, हरियाणा नगर निगम विज्ञापन उपनियम, 2018 को 28.03.2018 को अधिसूचित किया गया, जिसने 2016 के उपनियमों का स्थान ले लिया।

सरकार ने अधिक पारदर्शिता लाने, आम जनता को सशक्त बनाने और सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की क्षमता बढ़ाने के इरादे से 15.07.2022 को हरियाणा नगरपालिका विज्ञापन उपनियम 2022 को स्पष्ट निर्देश के साथ अधिसूचित किया कि सरकारी संस्थाओं/एजेंसियों की संपत्तियों पर विज्ञापन की अनुमति केवल ओपन ई–नीलामी के माध्यम से दी जा सकती है। जिसके लिए 11.10.2022 को एक ऑनलाइन पोर्टल भी शुरू किया गया है।

इन उपनियमों और पोर्टल की मुख्य विशेषताएं है:

- सभी विज्ञापन संस्थाएं (कंपनी/ट्रस्ट/व्यक्तिगत) राज्य स्तर पर पंजीकृत होंगी और एक बार पंजीकृत होने के बाद वे सभी नगर पालिकाओं में बोली लगाने के लिए पात्र होंगी।
- सभी अनुमतियों और नीलामियों का प्रबंधन और निगरानी ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से की जा रही है।
- राजस्व रिसाव को रोकने के लिए, नगरपालिका द्वारा अग्रिम त्रैमासिक भुगतान प्राप्त होने के बाद ही सभी अनुमतियां सक्रिय होंगी।

- निजी/अन्य सरकारी विभागों की साइटों की जांच के बाद (उप–नियम के अनुसार) नगरपालिका द्वारा ई–नीलामी की जाएगी।
- सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार नगरपालिका द्वारा आरक्षित मूल्य घोषित किया जाएगा।
- सफल नीलामी के बाद, नगरपालिका को प्रचलित अधिसूचित अनुमति शुल्क वसूल कर राशि क्रमशः मालिक और नगरपालिका के बीच 60:40 के अनुपात में साझा की जाएगी।
- अनुज्ञा धारक को एक तिमाही के भुगतान के समतुल्य जमानत राशी नगर निगम को जमा करना होगा, ताकि भुगतान में किसी भी चूक की स्थिति में जमानत राशी को सम्मिलित किया जा सके। जमानत राशि जमा होने पर अनुमति स्वतः निरस्त हो जाएगी।

आज तक पोर्टल ने निम्नलिखित उपलब्धि हासिल की हैः

- राज्य स्तर पर पोर्टल में 60 से अधिक संस्थाएं पंजीकृत हैं
- अब तक 414 नगरपालिका साइटों की ई–नीलामी की गई है, जिनमें से 114 साइटों की सफलतापूर्वक नीलामी की गई है
- इन 114 साइटों से, संचयी सफल वार्षिक नीलामी मूल्य 11.97 करोड़ रूपये है, जो जबकी आरक्षित मूल्य केवल 3.86 करोड़ रूपये है।
- हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन भी रैपिड मेट्रो रेल गुरूग्राम की संपत्तियों पर विज्ञापन की नीलामी के लिए इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहा है।

आयुक्त, नगर निगम गुरूग्राम ने पत्र दिनांक 20.02.2023 द्वारा सूचित किया है कि पिछले वर्षो के विज्ञापन शुल्क/प्रभारों से संबंधित आंकड़े/अभिलेख (जून 2022 से पहले की अवधि के लिए विज्ञापन की पुरानी अनुमतियों और शुल्कों) से संबंधित रिकार्ड पूर्ण नहीं है। इसलिए वसूल योग्य राशि, वसूल की गई राशि तथा वसुली में देरी के कारणों से सम्बन्धित जानकारी केवल उपलब्ध रिकार्ड अनुसार दी गई है।

गुम रिकार्ड के सम्बन्ध में तहकीकात जारी है, जिसमें 6 महीने का समय लग सकता है।